

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक
(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

56 / 2021
12-10-2020

मुंशी पुत्र रामपाल मीना निवासी ग्राम बाखरगंज तहसील उनियारा जिला टोंक
राज०

—अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला— टोक

—रेस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय
नायब तहसीलदार सोप दिनांक 18-9-2020 प्रकरण सं० 43/2020

उपस्थिति : (1) श्री बंसन्त कुमार जैन अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेण्ट

निर्णय

दिनांक 20-1-2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा ने अपने निर्णय दिनांक 18-9-2020 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 818 रकबा 0.87 है०, वाके ग्राम पायगा तह० उनियारा पर उड़द की फसल काश्त कर अतिक्रमण का दोषी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, पेलन्टी कायम करने व 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट व राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस निवेदन किया है कि अपीलान्ट के विरुद्ध पटवारी हल्का ग्राम पायगा ने राजकीय भूमि खसरा नम्बर 818 रकबा 0.87 है०, पर कब्जे की रिपोर्ट नायब तहसीलदार सोप के समक्ष पेश की जो गलत है। अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कब्जा नहीं है बल्कि अवैधानिक रूप से रिपोर्ट की है जो विधि एवं विधान के विपरीत है। इसलिए नायब तहसीलदार साहब का निर्णय दिनांक 18-9-2020 खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट नियत दिनांक 18-8-2020 को नायब तहसीलदार साहब के कार्यालय में उपस्थित हुआ था किन्तु न्यायालय में लिपिक के अतिरिक्त कोई नहीं था इसलिए न तो अपीलान्ट की हाजरी दर्ज की गई तथा न ही सुनने हेतु आगामी तारीख पेशी दी गई तथा अपीलान्ट को पुनः नोटिस जारी कर बुलवाने का आदेश कही थी किन्तु उसके बाद नायब तहसीलदार साहब द्वारा अपीलान्ट की बिना तामील ही




जिला कलेक्टर
टोंक

अनुपस्थिति दर्ज कर अपीलान्त के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही कर निर्णय किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्त को न तो गवाह पेश करने का अवसर मिला ओर न ही हल्का पटवारी से जिरह करने का अवसर दिया गया है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18-9-2020 निरस्त फरमाया जावे व 90 दिवस का सिविल कारावास निरस्त कर 174/रूपये की आरोपित शास्ति निरस्त फरमाई जावे।

अपीलान्त के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्त की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्त द्वारा विवादित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 818 रकबा 0.87 है,वाके ग्राम पायगा पर उड़द की फसल काशत कर अतिक्रमण किया है। अपीलान्त द्वारा इससे पूर्व भी अतिक्रमण कर फसल काशत की गई थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं० 2232 दिनांक 11-3-2020 से बेदखल किया गया था जो पत्रावली में उपलब्ध पूर्व दस्तावेजों से साबित है। अपीलान्त राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने की आदी है, ओर विवादित भूमि से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्त की विधिवत रूप से तामिल हुई है, किन्तु अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्त द्वारा राजकीय भूमि खसरा नम्बर 818 रकबा 0.87 है,वाके ग्राम पायगा पर उड़द कह फसल काशत कर अतिक्रमण किया है। जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानो से सिद्ध है। अपीलान्त द्वारा दिनांक 27-12-2021 व 29-12-2021 को न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मैंने विवादित भूमि खसरा नम्बर 818 रकबा 0.87 है,वाके ग्राम पायगा पर कोई नाजायज कब्जा नहीं है, जो कब्जा काशत था वो हटा लिया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित है।

फलतः अपील अपीलान्त आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप का निर्णय दिनांक 18-9-2020 इस शर्त के साथ अपास्त किया जाता है कि यदि अपीलान्त पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20-1-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, दोक
दोक